खण्ड : 15 संख्या : 23

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग–1

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

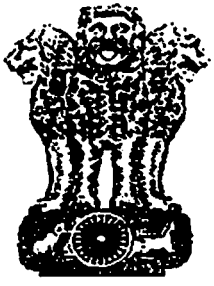

सत्यमेव जयते

सोमवार, तिथि : 26 अप्रैल, 1999

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार फटे पाइप की मरम्मती करने तथा अधूरी योजनाओं को पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

श्री मुंशी लाल राय : (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जलापूर्त्ति क्रम में यदा–कदा पाईप लीकेज होता है जिसकी मरम्मति कर दी जाती है। वर्तमान में पाईप फटा हुआ नहीं है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। स्वीकृत योजना के अनुसार कार्यान्वयन किया गया है लेकिन आबादी वृद्धि के कारण नई आबादी वाले क्षेत्र में पाईप लाईन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है।

(3) उपर्युक्त खंड 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार पुष्पम् का प्रश्न 257 खाद्य आपूर्त्ति विभाग से संबंधित है। माननीय मंत्री आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है ?

श्री मुंशील लाल राय : मैंने तारांकित प्रश्न संख्या– 684 का उत्तर दिया है।

उपाध्यक्ष : पुष्पम् जी का 257 का उत्तर माननीय मंत्री खाद्य आपूर्त्ति विभाग दें।

श्री रामचंद्र पूर्वे : इसका उत्तर भिजवा देंगे।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर भेज दिया जायेगा।

—

उप-समाहर्त्ता का पदस्थान

***686. श्री राम विनोद पासवान**– क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के अंतर्गत बखरी अंनुमंडल में भूमि सुधार उप–समाहर्ता

के पद रिक्त रहने से काफ़ी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार जनहित में भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता का अविलम्ब पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्री रमई राम : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है। मई माह में विभागीय स्थापना समिति द्वारा बेगुसराय जिला के बखड़ी अनुमंडल में उप—समाहर्त्ता, का पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

——

राजस्व क्षति को रोकने की व्यवस्था

*691. **श्री रघुवर दास**— क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के बिरसानगर में बिरसा सेवादल पंचायत समिति निबंधन विभाग द्वारा निबंधित नहीं है।

(2) क्या यह बात सही है कि बिरसानगर टाटा लीज के जमीन पर अवस्थित है तथा उक्त जमीन का नवीकरण नहीं होने की वजह से उक्त जमीन बिहार सरकार की है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का मालिकाना एवं आवासीय प्रमाण—पत्र उक्त समिति के 1,000 रूपये से 5,000 रूपये लेने के बाद ही नागरिकों को दिया जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त समिति को सरकार विरोधी कार्य करने के आरोप में भंग करते हुए सरकारी राजस्व की क्षति को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्री रमई राम : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। टिस्को की लीज अवधि 31—12—95 को समाप्त हो गयी है तथा लीज के नवीकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है।